

31
41

क्रमांक: ए.6॥44॥राज-6/2001/15

जयपुर, दिनांक: 4.5.02

आस्त विभागीय आभूक्त ।

आस्त विभागा कौन्सिलर ।

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक ए.6॥44॥राज-6/2001/22 दि. 6.12.2001 के अन्तर्गत गैर सुमोकेन एवं निवायक भूमियों पर कृषि हेतु किए गए अतिक्रमों के नियमन के संबंध में "अतिक्रम के आभेद के बावत" राज्य सरकार द्वारा लगातार कब्जे हेतु कीतम साक्ष्यों को मान्यता दिए जाने बाबत निर्देश दिए गए थे । इन निर्देशों में चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रम के नियमन के संबंध में कोई आदेश शामिल नहीं थे ।

इस विभाग के गोरमत्र/आदेश क्रमांक ए.6॥21॥राज-4/33/5 दि. 2.2.33 के अन्तर्गत चरागाह भूमि पर दि. 1.1.70 से पूर्व के अतिक्रम के नियमन किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए थे । अतः 31.12.69 तक चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रम, गोरमत्र दि. 2.2.33 के अन्तर्गत निहित निर्देशों को ध्यान में रखकर नियमन किए जा सकते हैं । चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमों के नियमन के संबंध में राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि लगातार कब्जे हेतु निम्न साक्ष्य प्राप्त होंगे :-

1. 1.1.70 से पूर्व का कब्जा रिहार्ड से प्रमाणित होना चाहिए ।
2. आज का कब्जा भी प्रमाणित होना चाहिए जो कम से कम गत दो वर्ष से लगातार कृषि होना चाहिए ।
3. बीच के वर्षों में लगातार कब्जे के संबंध में जिन वर्षों का कब्जा रिहार्ड में दर्ज नहीं है तो कारण लिखते हुए कब्जे की गुण्ट हेतु तत्सदक शुदा ग्राम्य-मत्र आदि दिए जा सोंगे । किन्तु ऐसे ग्राम्य-मत्र 31.2.69 से आज तक की अवधि के बीच के कुल 10 वर्ष तक की अवधि के लिए ही मान्य होंगे ।
4. यदि मूल कब्जाधारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों के मध्य में नियमोन्नेतकरण किया जावे । इनके संयुक्त छातेदारी दर्ज होगी ।
5. अगर किसी वर्ष मिसाल में अतिक्रमण किया तथा उसका नाम अतिक्रमी के रूप में रिहार्ड है तथा बीच के वर्षों में मिसाल के जीवितकाल में उसके बेटे आदि ने अतिक्रमण किया है तो, उसे अतिक्रमी के गोरवार का ही अतिक्रमण मानते हुए मूल कब्जाधारी या बिन्दु संख्या 4 के अनुसार कार्यवाही करती जावे ।

[Signature]

॥ जी० एस० सिंह ॥
राजस्व सचिव

प्रति धिपि: निम्नलिखितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभिन्न सचिव, राजस्व मंत्री महोदया 2. निजी सचिव, राजस्व सचिव ।

[Signature]
शासन उप सचिव